Seventeenth Loksabha

an>

Title : Regarding problems of water and electricity in Jharkhand.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष जी, मैं जिस इलाके से आता हूं, मेरे लोक सभा क्षेत्र से दो नदियां मयूराक्षी और चानन निकलती हैं । मैं यह एग्रीमेंट लेकर आया हूं । यह 19 जुलाई, 1978 का है जो तत्कालीन बंगाल के मुख्य मंत्री ज्योति बसु और बिहार के मुख्य मंत्री कर्पुरी ठाकुर जी के बीच हुआ था । जो नदी हमारे यहां से निकलती है, उसका पूरा का पूरा डैम मेरे यहां है, लेकिन उसका पूरा पानी बंगाल यूज करता है । मेरे यहां मैथंड डैम है, मेरे यहां पंचेत डैम है । ये झारखंड की जमीन पर बने हुए हैं लेकिन इनका पूरा पानी और पूरी बिजली पूरी की पूरी बंगाल यूज करता है । बंगाल ने वर्ष 1978 में एक एग्रीमेंट साइन किया और उसने कहा कि इसके बदले वह तीन डैम बनाएगा । अजय नदी के बदले वह काली पहाड़ी में डैम बनाएगा । मयूराक्षी नदी पर सिद्देश्वरी प्रोजेक्ट बनाएगा और एक बाराकर नदी पर डैम बनाएगा । बंगाल सरकार ने कहा कि तीन डैम अपने खर्चे पर हमें बनाकर देगा । 1978 से 40-41 साल हो गए हैं । आज तक बंगाल सरकार ने उसके बारे में कोई मीटिंग नहीं की । जमीन हमारी है, पानी हमारा है और उसका सारा उपयोग बंगाल कर रहा है । उसी तरह से दूसरी नदी चानन है जो मेरे लोक सभा क्षेत्र देवघर से निकलती है और उसका पूरा पानी बिहार सरकार यूज करती है । उसका पानी गोड्डा जिले को देना था और उस डैम को बने हुए 50 साल हो गए? 1966 में वह डैम बना और आज 52 साल बाद मैं इस बात को कह रहा हूं । मेरा आपसे आग्रह है कि इस तरह के जो इंटर-स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, जिसमें सरकारें एग्रीमेंट का पालन नहीं कर रही हैं । मेरा आग्रह है कि या तो भारत सरकार इसमें इंटरविन करे, बंगाल का पानी रोके, ... (व्यवधान) झारखंड को पानी दे । यदि झारखंड को पानी नहीं मिलेगा तो यहां के किसान मर जाएंगे और संथाल परगना में एक साल पानी पड़ता है, दो साल सुखाड़ होता है । हम पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं । पानी हमारा है, ज़मीन हमारी है, डैम हमारा है, लेकिन बंगाल सरकार इसका पालन नहीं कर रही है ।

इसीलिए उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और एक कमेटी बनानी चाहिए । धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष :

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।